

 सत्यमेव जयते	<b>राजस्थान राजपत्र</b> <b>विशेषांक</b>	<b>RAJASTHAN GAZETTE</b> <b>Extraordinary</b>
	<b>साधिकार प्रकाशित</b>	<b>Published by Authority</b>
	श्रावण 25, मंगलवार, शाके 1944-अगस्त 16, 2022 <i>Sravana 25, Tuesday, Saka 1944- August 16, 2022</i>	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

सहकारिता विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 04, 2022

**जी.एस.आर.60 :-**अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम, 2019 (2019 का केंद्रीय अधिनियम सं. 21) की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, केन्द्र सरकार के परामर्श से इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का नाम राजस्थान अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

**2. परिभाषाएं.-** (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

- (क) “अधिनियम” से अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम, 2019 (2019 का केंद्रीय अधिनियम सं. 21) अभिप्रेत है;
- (ख) “आवेदन” से अधिनियम की धारा 14 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा फाइल किया गया कोई आवेदन अभिप्रेत है;
- (ग) “प्राधिकारी” से अधिनियम की धारा 9 के अधीन अभिहित कोई प्राधिकारी अभिप्रेत है;
- (घ) “सक्षम प्राधिकारी” से अधिनियम की धारा 7 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई प्राधिकारी अभिप्रेत है;
- (ङ) “अभिहित न्यायालय” से अधिनियम की धारा 8 के अधीन राज्य सरकार द्वारा गठित कोई अभिहित न्यायालय अभिप्रेत है; और
- (च) “धारा” से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो उनके उस अधिनियम में हैं।

**3. सक्षम प्राधिकारी द्वारा संपत्ति की अनन्तिम कुर्की की रीति.-** (1) अनन्तिम कुर्की के आदेश की प्रति की तामील संपत्ति के स्वामी या किसी ऐसे व्यक्ति पर की जायेगी, जिसने संपत्ति

पर काबिज होने का दावा किया है या किसी अन्य ऐसे व्यक्ति पर की जायेगी, जिसका उक्त संपत्ति में कोई हित है।

(2) अनन्तिम कुर्की का आदेश ऐसे क्षेत्र या अधिकारिता में, जिसमें निक्षेप लेने वाला अवस्थित है, व्यापक रूप से परिचालित प्रमुख समाचार पत्र में, देशी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में, प्रकाशित किया जायेगा।

(3) जहां सक्षम प्राधिकारी, उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति को अनन्तिम कुर्की के आदेश की तामील करने में समर्थ नहीं होता है, वहां उप-नियम (2) के अधीन उपबंधित रीति में आदेश के प्रकाशन द्वारा आदेश की तामील समझी जायेगी।

(4) सक्षम प्राधिकारी, ऐसी स्थावर संपत्ति के सहजदृश्य स्थान पर अनन्तिम कुर्की के आदेश को चिपकाकर स्थावर संपत्ति का कब्जा लेगा।

(5) जहां कुर्क की जाने वाली संपत्ति कोई जंगम संपत्ति है, वहां सक्षम प्राधिकारी ऐसी संपत्ति का वास्तविक कब्जा लेगा और उसे अपनी अभिरक्षा में या उसकी सहायता के लिए नियुक्त किसी अन्य अधिकारी की अभिरक्षा में प्रतिधारित करेगा।

(6) सक्षम प्राधिकारी, अनन्तिम रूप से कुर्क संपत्ति के अभिलेख का अनुरक्षण करेगा, जिसमें संपत्ति के प्रबंध से उपगत किसी व्यय या उसकी लागत के ब्यौरे और संपत्ति से प्राप्त किसी आय के ब्यौरे सम्मिलित होंगे।

(7) सक्षम प्राधिकारी, निक्षेप लेने वाले की आस्तियों और दायित्वों का निर्धारण करेगा और ऐसे निक्षेपकर्ताओं के, जिनसे निक्षेप लेने वाले ने अविनियमित निक्षेप स्कीम के अनुसरण में निक्षेपों का संग्रहण किया है, संपूर्ण अभिलेख को तैयार करेगा।

(8) सक्षम प्राधिकारी, उप-नियम (7) के अधीन निक्षेप लेने वाले की आस्तियों और दायित्वों के निर्धारण के प्रयोजनों के लिए मूल्यांकक की नियुक्ति कर सकेगा।

(9) जहां कोई ऐसी संपत्ति, जिसका कब्जा लिया गया है, विनश्वर प्रकृति की है, वहां सक्षम प्राधिकारी निक्षेपकर्ताओं के उत्तम हित को ध्यान में रखते हुए उसका विक्रय कर सकेगा।

(10) सक्षम प्राधिकारी द्वारा, उप-नियम (9) के अधीन विक्रय के ब्यौरे और आगमों को उप-नियम (6) में यथाविनिर्दिष्ट अभिलेख में पृथक् रूप से प्रविष्ट और अनुरक्षित किया जायेगा।

**4. फरार व्यक्ति से संबंधित शक्तियां.-** जहां सक्षम प्राधिकारी या सक्षम प्राधिकारी की सहायता के लिए नियुक्त अधिकारियों का समाधान हो जाता है या विश्वास करने का कारण है कि व्यक्ति, जिसके संबंध में अधिनियम के अधीन कार्रवाई अनुध्यात है, फरार हो गया है या स्वयं को छिपा रहा है, वहां सक्षम प्राधिकारी या सक्षम प्राधिकारी की सहायता के लिए नियुक्त अधिकारी आगे की कार्रवाई के लिए अभिहित न्यायालय को लिखित में रिपोर्ट करेगा।

**5. संपत्तियों के अभिग्रहण की शक्ति.-** जहां सक्षम प्राधिकारी की सहायता के लिए नियुक्त अधिकारियों या सक्षम प्राधिकारी का समाधान हो जाता है या विश्वास करने का कारण है कि किसी संपत्ति के, जो अधिनियम के अधीन कुर्क किये जाने के दायित्वाधीन है, छिपाये जाने, अंतरित किये जाने या किसी ऐसी रीति में बरती जाने की संभावना है जिसके परिणामस्वरूप अधिनियम का

प्रयोजन विफल हो जायेगा, वह ऐसी संपत्ति का अभिग्रहण किये जाने का पुलिस अधिकारी को निदेश देगा या जहां ऐसी संपत्ति का अभिग्रहण किया जाना साध्य नहीं हो, वहां ऐसी संपत्ति को फ्रीज़ किये जाने का आदेश कर सकेगा और यह अंतरित या अन्यथा व्ययनित या बरती नहीं जायेगी।

**6. विधि व्यवसायी और अन्य को नियुक्त करने की शक्ति.-** सक्षम प्राधिकारी या सक्षम प्राधिकारी की सहायता के लिए नियुक्त कोई अधिकारी अभियोजन विभाग, विधि व्यवसायी, सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी, चार्टर्ड एकाउंटेंट या किसी अन्य व्यक्ति जिसकी सेवाएं अधिनियम के उपबंधों के निष्पादन और आस्तियों के कब्जे और वसूली के लिए आवश्यक हों, की सेवाओं का उपयोग करने का हकदार होगा।

**7. अभिलेखों का परिबद्धकरण और अभिरक्षण.-** (1) ऐसा व्यक्ति, जिसकी अभिरक्षा से अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (8) के अधीन अभिलेख परिबद्ध किये गये हैं, सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी की उपस्थिति में ऐसे स्थान और समय पर, जो सक्षम प्राधिकारी इस निमित्त नियत करे, उसकी प्रतियां बना सकेगा या उससे उद्धरण ले सकेगा।

(2) धारा 7 की उप-धारा (2) के अधीन नियुक्त अधिकारी, ऐसे अभिलेख को, सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन लिए बिना तीन मास तक की अवधि के लिए अपनी अभिरक्षा में रखेगा और यदि अभिलेख को उक्त अवधि के पश्चात् अवधारित करना आवश्यक है तो सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन अपेक्षित होगा।

(3) यदि कोई व्यक्ति, जिसकी अभिरक्षा से अभिलेख परिबद्ध किये गये हैं, अभिलेखों के परिबद्ध किये जाने के किसी कारण को आक्षेपित करता है तो वह सक्षम प्राधिकारी को ऐसे आक्षेप के कारणों को बताते हुए एक आवेदन कर सकेगा और सक्षम प्राधिकारी आवेदक को सुनवाई का अवसर दिये जाने के पश्चात् ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा वह ठीक समझे।

(4) अधिकारी, उसके द्वारा परिबद्ध किये गये और अभिरक्षा में प्रतिधारित किये गये अभिलेखों की सुरक्षित अभिरक्षा सुनिश्चित करेगा।

**8. स्वयं सहायता समूहों के लिए अधिकतम सीमा.-** किसी स्वयं सहायता समूह के सदस्य द्वारा किया गया दस हजार रुपये प्रति मास तक की राशि का कोई कालिक संदाय अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (4) में यथा परिभाषित निक्षेप का भाग नहीं होगा।

[प. 12(15)सह/2019/पार्ट-1]

राज्यपाल की आज्ञा से,

नारायण सिंह,

संयुक्त शासन सचिव।